20.31 hrs.

UTTAR PRADESH APPROPRIATION (VOTE ON ACCOUNT) BILL.* 1980

THE MINISTER OF FINANCE AND INDUSTRY (SHRI R. VENKATARAMAN): I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for the withdrawal of certain sums from and out of the Consolidated Fund of the State of Uttar Pradesh for the services of a part of the financial year 1980-81.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to provide for the withdrawal of certain sums from and out of the Consolidated Fund of the State of Uttar Pradesh for the services of a part of the financial year 1980-81."

The motion was adopted.

SHRI R. VENKATARAMAN: I introduce† the Bill.

I beg to move†:

"That the Bill to provide for the withdrawal of certain sums from and out of the Consolidated Fund of the State of Uttar Pradesh for the services of a part of the financial year 1980-81, be taken into consideration."

MR. DEPUTY-SPEAKER: Motion moved:

"That the Bill to provide for the withdrawal of certain sums from and out of the Consolidated Fund of the State of Uttar Pradesh for the services of a part of the financial year 1980-81, be taken into consideration."

श्री कृष्ण चन्द्र पांडे (बस्तीलाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका और इस सदन का आभारी हूं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश की समस्याओं को मंत्री जी को सुनाने का आपने मुझे मौका दिया । सबसे अधिक आभारी हूं गरीब मजदूरों की नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी का कि उन्होंने उत्तर प्रदेश की तानाशाही सरकार को भंग कर दिया ।

नारायणपुर की घटना को ले कर पूरे देश का सिर झुक गया । नारायणपुर में जो जांच चल रही है, वहां जो घटनाएं घटी हैं, उसके बारे में पूरे सदन के सदस्यों से मैं आग्रह करूंगा कि आप सब वहां जा कर वहां की दुर्दशा को देख कर आइए । वहां पर जिस तरह से बहु-बेटियों की इज्जत लुटी और जिस तरह से डाके डाले गये, जो कि लोक-दल सरकार ने कराये, मैं इन्दिरा जी का आभारी हूं कि उन्होंने वहां की तानाशाही सरकार को खत्म कर दिया ।

पूर्वी उत्तर प्रदेश की जो हालत है, यह उत्तर-प्रदेश का बजट है, इस बजट का पन्ना-पन्ना हम पूर्वी उत्तर प्रदेश के सदस्य उलट कर देख चुके हैं कि बस्ती, देवरिया, गाजीपुर और गोंडा व बहराइच के लिए क्या लिखा है, लेकिन इसमें कुछ भी देखने को मिला ही नहीं । पूर्वी उत्तर प्रदेश के साथ हमेशा हमेशा से इस तरह की उपेक्षा होती रही है, लेकिन मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से, वित्त मंत्री व दूसरे मंत्रियों से और मंत्रियों के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि पूर्वी उत्तर-प्रदेश इस समय बड़े ही संकट से गुजर रहा है और अगर पूर्वी उत्तर प्रदेश की उपेक्षा इसी तरह से की जायेगी, जैसी कि अब तक होती रही है तो यह हम लोगों के कब्जे से बाहर निकल जायेगी । यह मैं स्पष्ट अपने नेताओं से कहना चाहता हूं । बस्ती की क्या हालत है, बस्ती में कुछ नहीं है । प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी के आशीर्वाद से बहुत लड़ाई लड़ने के बाद मगहर में एक सूती मिल की स्थापना हुई । उद्घाटन इंदिरा जी ने किया । संजय जी को ले जा कर मैंने शिलान्यास कराया । नारायण दत्त जी उस समय मुख्य मंत्री थे । जब मिल की स्थापना हो पाई और मिल बनने लगी तो उत्तर प्रदेश की और हिन्दुस्तान की जनता बौखला गई, भ्रम में पड़ गई और जनता पार्टी की सरकार को यहां ला कर दिल्ली में बैठा दिया । पांच साल की जगह वह सरकार ढाई साल चली और क्या हुआ उस मगहर मिल का? वहां जो मिल लगी वह किस के लिए लगी ? गरीब मजदूरों और बुनकरों के लिए लगी । पूंजीपतियों के लिए वह मिल नहीं लगाई गई थी । इंदिरा जी ने आदेश दिया था कि गरीब बुनकरों के कल्याण के लिए मगहर में मिल लगाओ । वह संत कबीर का ऐतिहासिक स्थान है । मिल लग गई । जनता पार्टी की सरकार आ गई । आर० एस० एस० के लोगों की भर्ती हो गई उस सरकार में । सारा आर० एस०एस० भर गया । नतीजा क्या हुआ कि जो वहां

*Published in Gazette of India Extraordinary Part II, Section 2, dated 18-3-80

†Introduced moved with the recommendation of the President.

[श्री कृष्ण चन्द्र पांडे]

से सूत निलकता है एक आर०एस०एस० के पूंजीपति को वह सारा सौंप दिया जाता है । माननीय वित्त मंत्री जी इस को सुन लें, और वह पूंजीपति उस सूत का ब्लैक करता है । इस की वह जांच करवा लें । मैं उन को प्रमाण दे रहा हूं । तो जो सूती मिल लगी उस का फायदा बुनकरों को नहीं मिला । जिस समय हमारी सरकार यहां केन्द्र में थी 85 रुपया में बण्डल सूत मिलता था 32 नम्बर का और उस का जोड़ा उस समय 24 और 25 रुपये में बिकता था । आज क्या हालत है कि आज बुनकरों को मिल रहा है 106 रुपये बंडल सूत और वही कपड़ा आज खरीदा जा रहा है 24 और 25 रुपये में । हमारा पूर्वी उत्तर प्रदेश बुनकरों का क्षेत्र है, गरीबों का क्षेत्र है, मजदूरों का क्षेत्र है, सर्वहारा वर्ग का क्षेत्र है और वह लूटा जा रहा है पूंजीपतियों द्वारा । तो वित्त मंत्री जी से मेरा बिनम्र आग्रह है कि उस सूती मिल का वह जो एजेंट है जो कुल सूत खरीद ले रहा है उसके ऊपर प्रतिबन्ध लगाइए । उस को सारा सूत खरीदने से रोकिए ।

दूसरी प्रार्थना यह है हाथ जोड़ कर सारे संसद् सदस्यों से और आप के माध्यम से माननीय मंत्री जी से कि देश आजाद हुए 32 वर्ष हो गए लेकिन मेरे क्षेत्र में मेहदावल एक कस्बा है, आज भी वहां जमींदारी है । आज भी वहां की जमींदारी नहीं टूटी । मैंने बहुत पत्र लिखे उत्तर प्रदेश की सरकार को लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई । आज बागडोर श्रीमती इंदिरा गांधी के हाथ में है । आप के माध्यम से मैं प्रधान मंत्री जी से अपील करना चाहता हूं कि मेहदावल टाउन एरिया की जमींदारी तुरन्त तोड़ी जाय जिस से गरीब मजदूरों की रक्षा हो सके ।

एक बात और कहना चाहता हूं । जब जनता पार्टी की सरकार आई तो पूरे प्रदेश में जिला परिषदें कांग्रेस के हाथ में थीं । ज्यों ही जनता सरकार आई सारी जिला परिषदें भंग हो गई, सारी नोटिफाइड एरियाज और टाउन एरियाज भंग हो गईं । मेरी अपील है कि उत्तर प्रदेश की जिला परिषदें जो उस वक्त भंग की गई थीं उन को तुरन्त बहाल कराया जाय ।

पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कहानी जरा सुन लीजिए । हमारे भाई मुशीर साहब अभी बोल रहे थे । उन्होंने भी स्पष्ट कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मेरठ, आगरा और रुहेलखण्ड डिवीजन में गरीब मजदूर अपना वोट डालने नहीं गए । आप जो चुनाव कराने जा रहे हैं वह किस बल बूते पर कराने जा रहे हैं ? कौन वोट देने जायगा ? इस का प्रबन्ध पहले कीजिए कि गरीब मजदूर मेरठ, आगरा और रुहेलखण्ड डिवीजन में वोट डालने जाएं । फिर चुनाव करा लीजिए । चुनाव कराने से पहले आप का इस मुद्दे पर जरूर ध्यान रखना चाहिए । एक कमेटी बनी थी कांग्रेस के संसद सदस्यों की और और लोगों की, उस में हम लोग गए थे आगरा डिवीजन देखने । वहां पर पता लगा कि पोलिंग के दिन हत्याएं की गईं, मर्डर्स हुए । मेरी अपील है आप के माध्यम से वित्त मंत्री जी से, गृह मंत्री जी से और बाकी सारे मंत्रियों से कि आप इस डिवीजन को ठीक करें जिस से गरीब मजदूर वोट डालने जा पाएं ।

गन्ने की कहानी भी जरा सुन लीजिए । आज पूर्वी उत्तर प्रदेश में दूसरा भाव है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दूसरा भाव है । पूर्वी उत्तर प्रदेश में दूसरा भाव और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दूसरा भाव । मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी, देश के सारे नेताओं और कृषि मंत्री तथा प्रधान मंत्री जी से अपील करना चाहता हूं कि पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की इस विषमता को समाप्त किया जाए ।

इन शब्दों के साथ ही मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं और प्रस्तुत वित्त विधेयक का हार्दिक समर्थन करता हूं ।

श्री राम नगीना मिश्रा (सलेमपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया । मैं केवल दो मिनट ही बोलूंगा, इससे अधिक समय नहीं लूंगा क्योंकि सदन का समय बड़ा कीमती है । हमारे प्रदेश की बेहूदी के लिए सारे प्वाइंट यहां पर प्रस्तुत किए जा चुके हैं । मैं केवल देवरिया और बलिया के बारे में कुछ कहना चाहूंगा । देवरिया और बलिया वालों पर एक कविता है जिसका आभास शायद उनको पहले ही लग गया था :

जब वक्त गुलशन पर पड़ा तो लहू हमने दिया
जब बहार आई तो कहते हैं तुम्हारा काम नहीं ।

देवरिया बलिया वालों की आज यही हालत है । मेरा सिर्फ इतना ही निवेदन है कि यह सदन आज से बहुत पहले से ही जानता है और उत्तर प्रदेश की दशा से प्रभावित होकर हमारे परम आदरणीय नेता पं० जवाहरलल नेहरू ने पूर्वी जिलों के सुधार के लिए पहले आयोग की स्थापना की थी । उस आयोग की सिफारिशें सरकार के पास मौजूद हैं । मैं केवल यही चाहता हूं कि जिस सदन में पं० जवाहरलाल नेहरू रहे, देश के अन्य वरिष्ट नेता रहे उस सदन के माध्यम से पूर्वी उत्तर प्रदेश की गरीबी से प्रभावित होकर जो कमेटी बनाई गई, उसकी जो सिफारिशें हैं उनको पूर्वी उत्तर प्रदेश में लागू किया जाए ।

मेरा दूसरा निवेदन है कि बलिया जनपद में घाघरा के किनारे लीलकार गांव में हजारों मकान हैं, करोड़ों की सम्पत्ति है लेकिन नदी से दूरी अब केवल दो सौ गज की दूरी ही रह गई है । सरजू नदी बराबर काट रही है । इस संबंध में तत्काल यदि कोई व्यवस्था नहीं की गई तो करोड़ों की सम्पत्ति और हजारों घर नष्ट

हो जायेंगे । मैं खुद वहां पर जाकर देख आया हूं इसलिए मेरा निवेदन है कि इस संबंध में तत्काल कार्यवाही होनी चाहिए । इसी प्रकार से ग्राम हल्दी रामपुर भी घाघरा से कट रहा है। अगर समय रहते इन दोनों गांवों की हिफाजत नहीं की गई तो दोनों गांव कटकर घाघरा में विलीन हो जायेंगे ।

श्रीमन्, इस सदन में जब श्री कमलापति त्रिपाठी जी जहाजरानी मंत्री थे तब भागलपुर रोड पुल मंजूर हुआ था । फिर सरकार बदल गई, दूसरी सरकार आई तो उस पर अमल नहीं हुआ । भागलपुर रोड पुल पहले से स्वीकृत है, कोई आज की यह बात नहीं है इसलिए इसको बनाया जाना चाहिए ।

अभी इसके पहले मंत्री जी का उत्तर हमने सुना कि यदि उपयुक्त साधन हों तो वहां पर मशीनरी लगाई जा सकती है । देवरिया, सलेमपुर में बड़ी लाइन जा रही है, वहां पर 14 शुगर फैक्टरीज हैं, आपको काफी बगास मिल सकता है । पास में नैपाल का बार्डर है, काफी बांस मिल सकता है और धान की खेती से काफी प्याल मिल सकता है, इस प्रकार से यह सबसे ज्यादा सूटेबिल जगह है और अगर कोई इंडस्ट्री खोलनी है तो सलेमपुर में पेपर मिल जरूर खोली जानी चाहिए । साथ ही मैं यह निवेदन करूंगा कि पूर्वांचल में सलेमपुर ऐसी जगह है, जहां एक गांव से दूसरे गांव में जाना दूभर है । वहां पर सड़कें नहीं हैं, इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि वहां पर जो बड़े-बड़े गांव हैं, उनको मेन रोड से कनैक्ट कर दिया जाए ।

दूसरा निवेदन यह है कि इस प्रदेश में बिजली की कमी है। इसके पहले जो तीन प्रोजेक्ट्स सरकार ने स्वीकृत किए हैं—आनपारा, उचाहार, मनेरीमाली—इन तीनों पर तत्काल काम शुरू कर देना चाहिए । मेरा आपसे निवेदन है कि हमारे प्रदेश में बिजली के उत्पादन की जो मशीनें लगी हुई हैं, उनकी स्थापित क्षमता 3184 मेगावाट की है, किन्तु उनमें 1300 से 1400 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है, इसमें सुधार किया जाए । मेरी दृष्टि में इसका मुख्य कारण यह है कि अगर इसकी जिम्मेदारी टैक्नीकल हैण्ड्स पर डाल दी जाए और उनको जिम्मेदारी देकर यह कहा जाए कि आप काम नहीं करते हैं तो यह जिम्मेदारी आपकी है और सफलता भी होगी तो इसकी जिम्मेदारी आप की है, शायद इस तरह से मैं समझता हूं कि बिजली का उत्पादन बढ़ सकता है । मुझे ऐसा लगता है कि जो बड़े-बड़े प्रशासन करने वाले आई०सी०एस० आफिसर हैं, वे टैक्नीकल हैण्ड नहीं हैं, इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि यह जिम्मेदारी टैक्नीकल हैण्ड्स पर डालनी चाहिए ।

मान्यवर, उत्तर प्रदेश के पूर्व में जो शुगर फैक्ट्रियां हैं, वे जीर्ण हो चली हैं, उनकी रिकवरी केवल 8, 8.5, और 9 परसैंट है और किसानों का करोड़ों रुपया बाकी है, उनमें सुधार होना चाहिए, अगर सुधार नहीं हुआ तो पूर्वी जिला बर्बाद हो जाएगा । डीजल, मिट्टी का तेल आदि के संबंध में यह निवेदन करना है कि उनकी ठीक प्रकार से व्यवस्था होनी चाहिए । नैपाल तथा यू०पी० की सरहद पर विशेष पुलिस दस्ते कायम किए जायें ताकि स्मगलिंग को रोका जा सके । हमारे गांव के पास एक स्कूल है, उसकी हिफाजत होनी चाहिए और उसकी मदद की जानी चाहिए ताकि वह ठीक प्रकार से चल सके ।

इन शब्दों के साथ मैं आपका आभार प्रकट करते हुए कि आपने मुझे उत्तर प्रदेश बजट पर बोलने का अवसर दिया, आपको धन्यवाद देता हूं ।

MR. DEPUTY-SPEAKER: At this stage, if the Hon'ble Members confine themselves only to the important points instead of making elaborate speeches, that will be appreciated by everybody.

श्री महावीर प्रसाद (बांसगांव) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश को क्षेत्रीय असंतुलन के आधार पर इस माननीय सदन में माननीय वित्त मंत्री जी के द्वारा जो प्रस्ताव या बिल पारित करने के लिए निवेदन किया गया है, इस सदन में माननीय सदस्यों नें सुझाव दिये हैं, उसी के संबंध में मैं भी अपने को सम्मिलित करते हुए कुछ तथ्यों की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ।

उत्तर प्रदेश भारतवर्ष का सबसे पिछड़ा हुआ प्रदेश है, जहां पर 85 प्रतिशत लोग देहातों और गांवों में रहते हैं । हम दूसरे शब्दों में कहें तो उत्तर प्रदेश गावों का प्रदेश है और उत्तर प्रदेश की जनता, चाहे वह सिचाई के साधन हो, चाहे विद्युतीकरण व उद्योग के साधन हों, चाहे हरिजनोत्थान और शिक्षा के साधन हों, हर साधन में बहुत ही पिछड़ा हुआ है । इसलिए मैं चन्द शब्दों में आपके माध्यम से सरकार और माननीय वित्त मंत्री जी को कुछ सुझाव देना चाहता हूं । मैं ऐसे निर्वाचन क्षेत्र से चुनकर आया हूं जो कि उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल और गोरखपुर जिले का बांसगांव तहसील है, वह एक दम पिछड़ी हुई तहसील है । वहां पर घाघरा और कुवानों के बीच में एक विशाल क्षेत्र है जो कि नदियों के पास बसा हुआ है, लेकिन वहां पर सिंचाई की व्यवस्था नहीं हो सकी है। अब तक सरकार कहती थी कि वहां पर स्टेट ट्यूबवैल नहीं हो सकता है, लेकिन मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि वहां पर अभी जनता पार्टी की सरकार थी और वहां खाद्यान्न मंत्री श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव थे, उन्होंने

[श्री महावीर प्रसाद]

अपने गांव मणिकापुर में एक स्टेट ट्यूबवैल लगवाया है । जहां पर 30 साल तक ट्यूबवैल नहीं लगे थे वहां पर सिंचाई की व्यवस्था और स्टेट-ट्यूबवैल लगाया है । मैं आपके द्वारा माननीय वित्त मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वहां पर हर क्षेत्र में सिंचाई की व्यवस्था की जाए । सहजनवा से दोहरीघाट तक के लिए रेलवे लाइन की व्यवस्था करने के लिए मैं पहले ही रेल मंत्री जी से निवेदन कर चुका हूं, इसकी व्यवस्था की जानी चाहिए । हरिजनोत्थान के संबंध में मैं आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहता हूं कि अभी तक वहां पर पेयजल की व्यवस्था नहीं हो सकी है । जब हमारी कान्ग्रेस की सरकार थी, तो हरिजन विभाग से हरिजनों के लिए कूप निर्माण के लिए पैसा दिया जाता था ।

जब जनता पार्टी और लोक दल की सरकारें बनीं तो उन्होंने उसको समाप्त कर दिया । मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि उस व्यवस्था को फिर से चालू किया जाय और हरिजनों के पीने के पानी के लिए कूओं की व्यवस्था की जाय । आपको सुनकर ताज्जुब होगा आज भी हरिजनों को कूओं से पानी नहीं लेने दिया जाता है, आज भी उनको तालाबों और पोखरों के पानी को पीना पड़ता है ।

जहां तक उनके निवास की व्यवस्था का प्रश्न है, हमारी कांग्रेस सरकार के समय में 20 सूत्री कार्यक्रम के अधीन हरिजनों को तीन-तीन डिस्मिल जमीन दी गई थी । लेकिन जब जनता पार्टी और लोक दल की सरकारें बनीं, उस जमीन को उनसे छीन लिया गया । अब मैं आपके माध्यम से पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि उस व्यवस्था को पुनः लागू किया जाय । इसी तरह से विद्युतीकरण के सम्बन्ध में भी बीस सूत्री कार्यक्रम के अधीन हरिजन बस्तियों के विद्युतिकरण का नियम बना था, लेकिन बाद में उसको बन्द कर दिया गया । मैं चाहता हूं कि उसे फिर से लागू किया जाये ।

श्रीमन हमारे क्षेत्र में आवागमन के साधन सिंचाई के साधन, नहरों के साधन, स्टेट ट्यूब वेल के साधन, शिक्षा के साधन, स्कूलों के साधन, तथा अन्य सभी साधनों की व्यवस्था की जाय । इन कामों पर अविलम्ब कार्य शुरू किया जाय ताकि वे पिछड़े हुए क्षेत्र, विशेषकर उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल जो क्षेत्रीय असन्तुलन के आधार पर बहुत पिछड़ा हुआ है, आगे बढ़ सके ।

MR. DEPUTY-SPEAKER: The hon. Minister.

SHRI R. VENKATARAMAN: Mr. Deputy-Speaker, Sir, all the suggestions made by the hon. Members will be forwarded to the State Government for appropriate action. I only wish, to thank the hon. Members for the kindness and courtesy extended to me. I am deeply obliged to them.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That the Bill to provide for the withdrawal of certain sums from and out of the Consolidated Fund of the State of Uttar Pradesh for the services of a part of the financial year 1980-81, be taken into consideration."

The motion was adopted.

MR. DEPUTY-SPEAKER: We shall now take up the clauses.

The question is:

"That Clauses 2 and 3 and the Schedule stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clauses 2 and 3 and Schedule were added to the Bill.

Clause 1, Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI R. VENKATARAMAN: I move:

"That the Bill be passed."

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

*That the Bill be passed.

The motion was adopted.

20.53 hrs.

UTTAR PRADESH APPROPRIATION BILL*, 1980

THE MINISTER OF FINANCE AND INDUSTRY (SHRI R. VENKATARAMAN): I beg to move for leave to introduce a Bill to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of the State of Uttar Pradesh for the services of the financial year 1979-80.

---

*Published in Gazette of India Extraordinary, Part II, section 2, dated 18-3-80